(ग) तथा (घ) न्यायालयों द्वारा वर्ष 1985 से 1988 (जून तक) तक की अवधि के दौरान 1533 (अनन्तिम) अभियुक्त व्यक्तियों को दोषमुक्त किया गया है।

(ङ) तस्करी का देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ता है तथा इस तरह स्वदेशी उद्योग पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। हवाला लेनदेन के कारण इससे विदेशी मुद्रा की भी हानि होती है। तथापि, चूंकि तस्करी चोरी छिपे किये जाने वाला धन्धा है। अतः इससे हुई हानि का अनुमान लगाना सभव नहीं है।

बैंक ऋणों का बट्टे खाते डाला जाना

2449. **श्री शरद यादव :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वाणिज्यिक बैंकों द्वारा 1985 से अब तक गैर-सरकारी क्षेत्र की फर्मों को दिए गए ऋणों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या कुछ ऐसी फर्में हैं जो ऋण लेने के बाद दिवालिया हो गई ;

(ग) यदि हां, तो ऐसी फर्मों तथा उनके मालिकों के नाम क्या हैं ;

(घ) क्या ऐसी गैर-सरकारी क्षेत्र की फर्मों को दिए गए ऋणों को वाणिज्यिक बैंकों द्वारा बट्टे खाते डाल दिया गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो बट्टे खाते डाली गई ऋण-राशि का ब्यौरा क्या है और ऐसी फर्मों के नाम क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुवर्डो फेलेरियो) : (क) से (ङ) बैंकों की वर्तमान आंकड़ा सूचना प्रणाली से प्रश्न में पूछे गए ढंग से सूचना प्राप्त नहीं होती। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वह बैंकिंग प्रणाली से एक करोड़ रुपये और उससे अधिक की ऋण सीमा प्राप्त करने वाली प्राइवेट पार्टियों के संबंध में तिमाही आधार पर सूचना एकत्र करता है। गत तीन वर्षों के वास्ते दिसम्बर के अंत की स्थिति के अनुसार उपलब्ध सूचना निम्नानुसार है :—

वर्ष	उधारकर्ताओं की संख्या	कुल स्वीकृत सीमा (सावधि ऋणों सहित)	बकाया रकम
1985	3587	15781	10801
1986	4299	18285	12718
1987	4940	21842	15095

सरकारी क्षेत्र के बैंकों को नियंत्रित करने वाले कानूनों और बैंकरों में प्रचलित प्रथाओं एवं रीतिरिवाजों के अनुसार, बैंकों के अलग-अलग ग्राहकों से संबंधित सूचना प्रकट नहीं की जा सकती।

Deletion of 'on Demand' words from currency notes

2450. SHRI SHANKARRAO NARAYANRAO DESHMUKH: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that words "On Demand" have been deleted from the currency notes of the denomination of Rs. 100/-, Rs. 50/-, Rs. 20/- and Rs. 10/- if so, since when;

(b) what are the reasons for the deletion;

(c) what are the implications of this deletion; and

(d) whether Government have issued any Press Note in this regard allying the apprehensions on the minds of general public?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI EDUARDO FALEIRO): (a) to (d) The words 'On Demand' were deleted in the year 1968 to facilitate the incorporation of Hindi version of the promise clause in the Bank Notes. It had no other implication. The Reserve Bank of India had issued a Press Release informing the general public of the revised clause during the year 1968.